e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 11, November 2021

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 5.928

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com www.ijmrset.com

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - (एनईपी 2020)

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सारांश

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। [1] नई नीति शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 की जगह लेती है । [ए] यह नीति प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। [2]नीति जारी होने के तुरंत बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी भी क्षेत्रीय भाषा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। [3] एनईपी में भाषा नीति एक व्यापक दिशानिर्देश और प्रकृति में सलाहकार है; और यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर है कि वे कार्यान्वयन पर निर्णय लें। [4] भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। [5] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग पर 'जोर' दिया गया है , जबकि इसे कक्षा 8 और उससे आगे तक जारी रखने की सिफारिश की गई है। [14] संस्कृत और विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। नीति अनुशंसा करती है कि सभी छात्र अपने स्कूल में 'सूत्र' के तहत तीन भाषाएँ सीखेंगे। तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रों पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। [15]नीति जारी होने के तुरंत बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि एनईपी में भाषा नीति एक व्यापक दिशानिर्देश है; और यह कि कार्यान्वयन का निर्णय राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर था। [4] 2021 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में एक अधिक विस्तृत भाषा रणनीति जारी की जाएगी। [4] यह भी नोट किया गया था कि पहले से ही ऐसे संस्थान थे जिन्होंने 60 साल पहले इस भाषा नीति को लागू किया था जैसे कि सरदार पटेल विद्यालय । [4] 1986 की शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दोनों ने एक सलाहकार दिशानिर्देश के रूप में भी मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। [3]

परिचय

आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान दें: नीति ग्रेड 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। नीति में कहा गया है, "शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना होगा। 2025 तक। इस नीति के बाकी हिस्से हमारे छात्रों के लिए तभी प्रासंगिक होंगे जब यह सबसे बुनियादी सीखने की आवश्यकता (यानी, मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित) पहले हासिल की जाती है। इसके लिए, मूलभूत साक्षरता पर एक राष्ट्रीय मिशन और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अंकगणित की स्थापना की जाएगी।तदनुसार, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए तुरंत एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगी,2025 तक प्राप्त किए जाने वाले चरण-वार लक्ष्यों और लक्ष्यों की पहचान करना और उनकी प्रगति पर बारीकी से नज़र रखना और निगरानी करना"।[16] इसके बाद, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 जुलाई 2021 को निपुन भारत मिशन शुरू किया गया था। [17] " 10 + 2 " संरचना को " 5+3+3+4 " मॉडल से बदल दिया जाएगा। [18] इसे निम्नानुसार लागू किया जाएगा: [19] [20]

आधारभूत चरण: इसे आगे दो भागों में विभाजित किया गया है: प्रीस्कूल या आंगनवाड़ी के 3 साल , उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2। इसमें 3-8 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। पढ़ाई का फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर रहेगा।प्रारंभिक चरण: कक्षा 3 से 5 तक, जिसमें 8-11 वर्ष की आयु शामिल होगी। यह धीरे-धीरे बोलना, पढ़ना, लिखना, शारीरिक

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

शिक्षा, भाषा, कला, विज्ञान और गणित जैसे विषयों का परिचय देगा।मध्य चरण: कक्षा 6 से 8, 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करते हुए। यह छात्रों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी के विषयों में अधिक अमूर्त अवधारणाओं से परिचित कराएगा।माध्यमिक चरण: कक्षा 9 से 12 तक, 14-19 वर्ष की आयु को कवर करते हुए। इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है: कक्षा 9 और 10 पहले चरण को कवर करते हैं जबकि कक्षा 11 और 12 दूसरे चरण को कवर करते हैं। इन 4 वर्षों के अध्ययन का उद्देश्य गहराई और आलोचनात्मक सोच के साथ-साथ बहु-विषयक अध्ययन को विकसित करना है। विषयों के कई विकल्प प्रदान किए जाएंगे।प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में होने वाली परीक्षाओं के बजाय , स्कूली छात्र कक्षा 2, 5 और 8 में केवल तीन परीक्षाओं में भाग लेंगे। [18]

कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी लेकिन इसे फिर से डिजाइन किया जाएगा। इसके लिए मानक एक मूल्यांकन निकाय, PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) द्वारा स्थापित किए जाएंगे। . [21] परीक्षा में ही दो भाग होंगे, अर्थात् वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक। [1]इस नीति का उद्देश्य छात्रों के पाठ्यक्रम भार को कम करना और उन्हें अधिक "अंतर-अनुशासनात्मक" और "बहुभाषी" होने देना है। एक उदाहरण दिया गया था "यदि कोई छात्र भौतिकी के साथ फैशन की पढ़ाई करना चाहता है, या यदि कोई रसायन विज्ञान के साथ बेकरी सीखना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी"। [22] रिपोर्ट कार्ड "समग्र" होंगे, जो छात्र के कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। [1]कोडिंग कक्षा 6 से शुरू की जाएगी और अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा [23]

मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार नाश्ते को शामिल करने के लिए किया जाएगा। परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तैनाती के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। [24]उच्च शिक्षा: यह कई निकास विकल्पों के साथ एक स्नातक कार्यक्रम में 4 साल की बहु-अनुशासनात्मक स्नातक की डिग्री का प्रस्ताव करता है। इनमें पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल होंगे और इन्हें निम्नानुसार लागू किया जाएगा: [25]

1 साल का अध्ययन पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र

2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्लोमा

3 साल के कार्यक्रम के पूरा होने के बाद स्नातक की डिग्री

4 साल की बहु-विषयक स्नातक की डिग्री (पसंदीदा विकल्प)

एमफिल (मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी) पाठ्यक्रमों को डिग्री शिक्षा को पश्चिमी मॉडल के साथ संरेखित करने के लिए बंद किया जाना है। [26]उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना की जाएगी। परिषद का लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा। [18] एचईसीआई में 4 कार्यक्षेत्र होंगे:

[27]राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी), चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए। [28]राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी), एक "मेटा-मान्यता प्राप्त निकाय"। [28]

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्त पोषण और वित्तपोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी)। यह मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह लेगा । [28]सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), "स्नातक विशेषताओं" को फ्रेम करने के लिए, अर्थात् अपेक्षित सीखने के परिणाम। यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) तैयार करने में भी जिम्मेदार होगा। [28] राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक पेशेवर मानक सेटिंग निकाय (PSSB) के रूप में GEC के अंतर्गत आएगी। [29]अन्य पीएसएसबी में पेशेवर परिषद जैसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद , वास्तुकला परिषद , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद शामिल होंगे। [27]नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब जेईई मेन और एनईईटी के अलावा देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी । [30]नीति का प्रस्ताव है कि IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थान सीखने की विविधता के संबंध में परिवर्तन करते हैं। [18]नीति में भारत में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है। [31]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

विदेशी विश्वविद्यालय अब भारत में परिसर स्थापित कर सकते हैं। [32]निजी और सार्वजनिक दोनों विश्वविद्यालयों की फीस तय की जाएगी। [31]

विचार - विमर्श

NEP 2020 शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा के मामले में कई नीतिगत बदलावों को सामने रखता है। [37] शिक्षक बनने के लिए 2030 तक 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन न्यूनतम आवश्यकता होगी । [38] शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा। [38] राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 2021 तक शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और 2022 तक शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार करेगी। [38] नीति का लक्ष्य है: [39]

सुनिश्चित करें कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी छात्रों को भावुक, प्रेरित, उच्च योग्य, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है।

अन्य परिवर्तन-एनईपी 2020 के तहत कई नए शैक्षणिक संस्थानों, निकायों और अवधारणाओं को गठन की विधायी अनुमति दी गई है। इनमें शामिल हैं: [1]

- भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग [42]
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का एक डिजिटल स्टोरेज है जो आगे की शिक्षा के लिए क्रेडिट का उपयोग करके शिक्षा को फिर से शुरू करने में मदद करता है [43]
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, अनुसंधान और नवाचार में सुधार के लिए [44] [45]
- विशेष शिक्षा क्षेत्र, वंचित क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले समूह की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए [46]
- महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा में राष्ट्र की सहायता के लिए लिंग समावेशन कोष [47]
- नीति में भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान और पाली , फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान/संस्थान जैसे नए भाषा संस्थानों का प्रस्ताव है । प्रस्तावित अन्य निकायों में नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी शामिल हैं।

परिणाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) मसौदा पैनल के अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन ने टिप्पणी की, "कोई भाषा नहीं थोपी जा रही है। बहुभाषी लचीलापन अभी भी नए एनईपी 2020 का आधार है"। [48] यूजीसी ने कहा है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच नीति के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। [49] प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति 'क्या सोचें' के बजाय 'कैसे सोचें' पर केंद्रित है। [50]

IIT कानपुर के निदेशक, अभय करंदीकर ने नई नीति का समर्थन किया, जबकि IIT दिल्ली के निदेशक, वी। रामगोपाल राव ने नई शिक्षा नीति की तुलना संयुक्त राज्य के मॉरिल भूमि-अनुदान अधिनियमों से की और इसे भारत के लिए "मॉरिल मोमेंट" कहा। [51] जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति , एम. जगदीश कुमार , साथ ही जेएनयू के कुलपति ने नीति को "सकारात्मक कदम" कहा, जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने कहा। नीति "ग्राउंड ब्रेकिंग"। [52] [53]दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा, "नीति रोड मैप को बहुत अच्छी तरह से निर्धारित करती है"। [53] भारत के उपराष्ट्रपति , वेंकैया नायडू ने नीति के लचीलेपन का स्वागत किया और स्कूल से बाहर के बच्चों को स्कूल प्रणाली में लाने और स्कूल छोड़ने वालों को कम करने के अपने "उच्च" लक्ष्य की सराहना की। [54]लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता शशि

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

थरूर ने इस फैसले का स्वागत किया लेकिन नई नीति के कार्यान्वयन के बारे में अपनी चिंताओं को बताया। [55] ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। [56]

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के धीरज कुमार नाईट ने कहा कि एमफिल पाठ्यक्रम को हटाना एनईपी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि स्नातक स्तर पर कई निकास बिंदु पेश किए गए थे, लेकिन पीएचडी में रुचि रखने वाले। कोई त्वरित निकास बिंदु नहीं होगा, जो एमफिल ने प्रदान किया था। [26] जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने भारत में COVID-19 महामारी के बीच नीति को मंजूरी देने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इसके मसौदा चरण के बाद से नीति का विरोध किया था। [57] माकपा नेता सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि शिक्षाविदों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि पोलित ब्यूरो नेपार्टी ने नीति द्वारा प्रोत्साहित व्यावसायीकरण की निंदा की। [58] सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, जेएनयू के कुमकुम रॉय ने कहा कि लिंग अध्ययन, मीडिया, पर्यावरण और विकास, संस्कृति, दलित, भेदभाव और बहिष्करण, और मीडिया के अध्ययन के विषयों का विकास के लिए उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अध्ययन में मौलिक अधिकारों को छोड़ दिया गया है। [59] डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि नीति संसद में चर्चा के बिना पारित की गई थी और शिक्षा के हर स्तर पर संस्कृत के "अनिवार्य" विकल्प के कारण तमिल भाषा को कमजोर कर देगी। [60] जेएनयूएसयू की आइशी घोषट्वीट किया कि नीति के तहत इंटर्नशिप से बाल श्रम को बढ़ावा मिलेगा। [61] [62]2019 के मसौदे एनईपी की कई कारणों से आलोचना की गई थी। एक सोशल मीडिया अभियान ने दक्षिण भारतीय राज्यों के स्कूलों में हिंदी को शामिल करने का विरोध किया। [63] [64] द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इसने शैक्षिक संरचना के संघीय चरित्र, व्यावसायिक शिक्षा और स्वतंत्र अनुसंधान गतिविधि को कमजोर कर दिया है। [65] फ्रंटलाइन के मधु प्रसाद ने बताया कि कैसे मसौदे के "योग्यता-आधारित" कॉलेज प्रवेश मानदंड में आरक्षण और जाति- आधारित भेदभाव और देश में कई लोगों के उत्पीड़न को ध्यान में नहीं रखा गया। [66] डीपी शर्माभारतीय शिक्षा प्रणाली के अंत से अंत परिवर्तन की वर्तमान पहल की सराहना की, लेकिन सावधानी और ईमानदारी के साथ कार्यान्वयन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और, [67] [68] ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को शिक्षा परिवर्तन के साथ जोड़ा। [69]

निष्कर्ष

अगस्त 2021 की शुरुआत में, कर्नाटक एनईपी को लागू करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। [70]26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश ने NEP 2020 लागू किया।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को 2022 तक चरणों में लागू किया जाएगा। [71]तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य में नई घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) को लागू करने का निर्णय लिया है। [72]महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्देश दिया। [73]आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू करने का निर्देश दिया है। [74]राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि एनईपी 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। [75]असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एनईपी 2020 को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। [76]

संदर्भ

1. नंदिनी, एड। (29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020 हाइलाइट्स: बड़े बदलाव देखने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा"। हिंदुस्तान टाइम्स। 30 जुलाई 2020 को लिया गया।
2. ^ जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020)। "द हिंदू एक्सप्लेन्स | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है?" . द हिंदू। आईएसएसएन 0971-751X । 2 अगस्त 2020 को लिया गया।
3. ^ विश्नोई, अनुभूति (31 जुलाई 2020)। "एनईपी '20: एचआरडी के साथ अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्देश माध्यम में कोई स्विच नहीं"। द इकोनॉमिक टाइम्स। 31 जुलाई 2020 को लिया गया।
4. ^ गोहेन, मानश प्रतिम (31 जुलाई 2020)। "एनईपी भाषा नीति व्यापक दिशानिर्देश: सरकार"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 31 जुलाई 2020 को लिया गया।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

5. ^ चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020)। "समझाया: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना" । इंडियन एक्सप्रेस । 2 अगस्त 2020 को लिया गया ।
6. ^ चतुर्वेदी, अमित (30 जुलाई 2020)। " 'परिवर्तनकारी': नेता, शिक्षाविद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं" । हिंदुस्तान टाइम्स । 30 जुलाई 2020 को लिया गया । जबकि आखिरी नीति 1992 में घोषित की गई थी, यह अनिवार्य रूप से 1986 की एक रीहैश थी।
7. ^ "स्कूलों के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाला पैनल" । indianexpress.com। 22 सितंबर 2020
8. ^ "राज्य शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय निकाय द्वारा विनियमित होंगे: मसौदा एनईपी" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 21 नवंबर 2019 को लिया गया ।
9. ^ "यहां है क्यों आप नए एनईपी पर आनन्दित हो सकते हैं। और आप क्यों नहीं कर सकते" । तार । 31 जुलाई 2020 । 2 अगस्त 2020 को लिया गया ।
10. ^ जेबराज, प्रिसिला; हेब्बर, निस्तुला (31 जुलाई 2020)। रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं, "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने से पहले गहन विचार-विमर्श किया गया । " द हिंदू । आईएसएसएन 0971-751X । 2 अगस्त 2020 को लिया गया ।
11. ^ रोहतगी, अनुभा, एड. (7 अगस्त 2020)। "हाइलाइट | एनईपी भारत में अनुसंधान और शिक्षा के बीच की खाई को कम करने में भूमिका निभाएगा: पीएम मोदी" । हिंदुस्तान टाइम्स । 8 अगस्त 2020 को लिया गया ।
12. ^ राधाकृष्णन, अकिला (16 सितंबर 2020)। "नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करें और स्किलिंग एज के लिए स्कूल" । हिंदी केंद्र । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
13. ^ "सरकार ने शिक्षा पर राज्य के खर्च को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी" । लाइवमिंट । 29 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
14. ^ "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी: प्रमुख बिंदु" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 29 जुलाई 2020 । 29 जुलाई 2020 को लिया गया ।
15. ^ "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण" । एनडीटीवी डॉट कॉम । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
16. ^ "कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया" । pib.gov.in।
17. ^ "शिक्षा मंत्रालय ने निपुन भारत मिशन शुरू किया" । @बिजनेसलाइन । 8 अगस्त 2020 को लिया गया ।
18. ^ श्रीनिवासन, चंद्रशेखर, एड। (29 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020: कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण: नई शिक्षा नीति पर 10 अंक" । एनडीटीवी । 29 जुलाई 2020 को लिया गया ।
19. ^ कुलकर्णी, सागर (29 जुलाई 2020)। "नई नीति स्कूली शिक्षा का 5-3-3-4 मॉडल पेश करती है" । डेक्कन हेराल्ड । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
20. ^ कुमार, शुचिता (31 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति: 10+2 से 5+3+3+4 प्रणाली में बदलाव" । टाइम्स नाउ । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
21. ^ "साल में दो प्रयासों के साथ आसान बोर्ड परीक्षा: मसौदा शिक्षा नीति में एचआरडी सुझाव" । इंडिया टुडे । प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू. 4 नवंबर 2019 । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
22. ^ "केंद्र ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की" । द ट्रिब्यून । इंडिया। 29 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
23. ^ "नई शिक्षा नीति: छात्रों को कक्षा 6 से कोडिंग सीखना" । द क्विंट । 29 जुलाई 2020 । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
24. ^ कुमार, प्रकाश (30 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मध्याह्न भोजन के अलावा स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते का प्रस्ताव" । आउटलुक । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
25. ^ "नि: शुल्क प्रवेश- एनईपी 2020 में छात्रों के लिए बाहर निकलने के विकल्प पेश किए गए" । एनडीटीवी डॉट कॉम । 21 सितंबर 2020 को लिया गया ।
26. ^ भूरा, स्नेहा (30 जुलाई 2020)। "एमफिल के बचाव में: क्यों न डिग्री बंद कर दी जाए" । द वीक । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
27. ^ कुमारी, अनीशा, एड. (30 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: यूजीसी, एआईसीटीई, एनएएसी का एक नए निकाय में विलय" । एनडीटीवी डॉट कॉम । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

28. ^ शुक्ला, अमनदीप (29 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: यूजीसी, एआईसीटीई का युग खत्म, एनईपी ने एचईसीआई, 4 वर्टिकल के साथ एकल नियामक" पर विचार किया । हिंदुस्तान टाइम्स । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
29. ^ शुक्ला, अमनदीप (29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020: एनईपी शिक्षकों के लिए पेशेवर मानकों पर विचार करता है" । हिंदुस्तान टाइम्स । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
30. ^ "राष्ट्रीय शिक्षा नीति: उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एनटीए" । इंडियन एक्सप्रेस । 29 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
31. ^ कृष्णा, अतुल (29 जुलाई 2020)। "एनईपी 2020 हाइलाइट्स: स्कूल और उच्च शिक्षा" । एनडीटीवी । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
32. ^ कुमार, मनोज (29 जुलाई 2020)। "भारत नई शिक्षा नीति के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खोलता है" । रॉयटर्स । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
33. ^ लेन, जेसन (1 जुलाई 2013)। "विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत के नए नियम एक 'चूक अवसर' हैं " . उच्च शिक्षा का क्रॉनिकल ।
34. ^ "यूजीसी शीर्ष विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने की अनुमति देता है" । विश्वविद्यालय विश्व समाचार । 23 जनवरी 2020 को लिया गया ।
35. ^ "भारत के नॉलेज हब के रूप में उभरने का समय आ गया है, फिर से 'विश्व गुरु' बनें: उपराष्ट्रपति" । द हिंदू । पीटीआई। 5 सितंबर 2020। आईएसएसएन 0971-751X ।
36. ^ लेन, जेसन; शूएलर। "क्या अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर राष्ट्रीय पहचान में सहायता कर सकते हैं?" . विश्वविद्यालय विश्व समाचार । 24 जनवरी 2020 को लिया गया ।
37. ^ राजीव, केआर (31 जुलाई 2020)। "शिक्षक शिक्षा बड़े बदलाव के लिए तैयार" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
38. ^ "2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय बीएड डिग्री न्यूनतम योग्यता होगी, नया एनईपी कहता है" . लाइवमिंट । पीटीआई। 30 जुलाई 2020 । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
39. ^ "रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है" । डेक्कन क्रॉनिकल । 20 जून 2019 । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
40. ^ बराल, मैत्री, एड. (30 जुलाई 2020)। "एनईपी 2020: नई शिक्षा नीति ने प्रौद्योगिकी फोरम के गठन पर विचार किया" । एनडीटीवी । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
41. ^ "नीति आयोग ने स्कूलों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए BYJU'S के साथ समझौता किया" । इंडियन एक्सप्रेस । 17 सितंबर 2020 ।
42. ^ उपाध्याय, दीपक (29 जुलाई 2020)। "नई स्कूली शिक्षा नीति को मंजूरी: ग्रेडिंग सिस्टम, विषयों का अधिक विकल्प" । लाइवमिंट । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
43. ^ "सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए, नई शिक्षा नीति में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रस्ताव है; एकाधिक प्रवेश, निकास बिंदु" । समाचार18 . 29 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
44. ^ जयन, टीवी (5 जुलाई 2020)। "नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए" । @बिजनेसलाइन । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
45. ^ शुक्ला, अमनदीप (1 अक्टूबर 2019)। "एचआरडी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की" । हिंदुस्तान टाइम्स । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
46. ^ शुक्ला, अमनदीप (30 जुलाई 2020)। "सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए" हिंदुस्तान टाइम्स । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
47. ^ पंडित, अंबिका (30 जुलाई 2020)। "लिंग समावेशन निधि, विशेष शिक्षा क्षेत्र नीति में" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
48. ^ "नई शिक्षा नीति में कोई भाषा थोपना नहीं, मसौदा पैनल प्रमुख का कहना है" . इंडिया टुडे । नई दिल्ली । 30 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
49. ^ "यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों, शिक्षकों के बीच नई शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा" । हिंदुस्तान टाइम्स । 6 अगस्त 2020 । 6 अगस्त 2020 को लिया गया ।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

50. ^ "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एनईपी पर लाइव: 'क्या सोचें' से 'कैसे सोचें' पर ध्यान केंद्रित करने की नीति " । इंडिया टुडे । 7 अगस्त 2020। 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
51. ^ चंदा, पापड़ी (30 जुलाई 2020)। "आईआईटी निदेशकों ने नई शिक्षा नीति की सराहना की, इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और भारत के लिए 'मॉरिल मोमेंट' कहा । " टाइम्स नाउ । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
52. ^ "जेएनयू, जामिया वी-सीएस: राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे बढ़ो, सकारात्मक" । इंडियन एक्सप्रेस । 30 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
53. ^ "राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षाविदों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा करती है" । आउटलुक इंडिया । पीटीआई। 29 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
54. ^ नायडू, एम. वेंकैया (8 अगस्त 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी" । टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
55. ^ चतुर्वेदी, अमित (30 जुलाई 2020)। " 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत स्वागत है लेकिन...': शशि थरूर ने कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला" । हिंदुस्तान टाइम्स । नई दिल्ली । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
56. ^ जैन, संगीत (6 अगस्त 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समय के लिए एक नीति" । ओआरएफ । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
57. ^ सरफराज, कायनात (29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, सिसोदिया ने एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के कदम का स्वागत किया" । हिंदुस्तान टाइम्स । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
58. ^ "एनईपी लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा, मोदी कहते हैं, सीपीएम इसे शिक्षा को नष्ट करने के लिए एकतरफा अभियान" कहते हैं । फ़र्स्टपोस्ट । 30 जुलाई 2020 । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
59. ^ रॉय, कुमकुम (31 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया है, क्या नहीं इसकी बारीकी से जांच की जरूरत है" । इंडियन एक्सप्रेस ।
60. ^ "एनईपी 2020" तमिल को कमजोर करता है, इसके कार्यान्वयन को रोकता है: स्टालिन " । टाइम्स ऑफ इंडिया । पीटीआई। 9 अगस्त 2020 । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
61. ^ "आइशी घोष ने इंटर्नशिप को 'बाल श्रम' कहा, ट्विटर ने 'फ्रीलोडर कम्युनिस्ट' का मजाक उड़ाया " । फ्री प्रेस जर्नल । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
62. ^ शुक्ला, आशीष (30 जुलाई 2020)। "NEP 2020 में मोदी सरकार के 3-भाषा के फॉर्मूले से नेटिज़न्स नाराज़" । इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स । भारत । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
63. ^ स्टालिन, जे सैम डेनियल (1 जून 2019)। दत्ता रॉय, दिव्यांशु (सं.)। "#StopHindiImposition विरोध प्रदर्शन केंद्र की मसौदा शिक्षा योजना के खिलाफ" । एनडीटीवी । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
64. ^ स्टालिन, जे सैम डेनियल (3 जून 2019)। श्रीनिवासन, चंद्रशेखर (सं.). "तमिल भाषी मंत्री हिंदी विरोधी हंगामे के रूप में अग्निशामक में शामिल होते हैं" । एनडीटीवी । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
65. ^ दास, प्रजन्मा (29 जुलाई 2019)। "छह कारण क्यों एसएफआई सोचता है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा को नष्ट कर देगी जैसा कि हम जानते हैं" । द न्यू इंडियन एक्सप्रेस । 24 अप्रैल 2020 को लिया गया ।
66. ^ प्रसाद, मधु (19 जुलाई 2019)। "एनईपी 2019: द डेविल इन द डिटेल" । फ्रंटलाइन । 31 जुलाई 2020 को लिया गया ।
67. ^ "डॉ डीपी शर्मा ऑन द चैलेंजेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स" । एडुवॉइस |शिक्षा उद्योग की आवाज । 25 मई 2020 । 29 सितंबर 2020 को लिया गया ।
68. ^ "भारतीय विज्ञान विश्वविद्यालय (बीएसडीयू) ने 'संक्रांति की दिशा में दिशा की दिशा में इन प्रभामंडल की ओर' पर स्विच किया वेबिनार का " न्यूज़ ट्रैक (हिंदी में)। 2 मई 2020 । 29 सितंबर 2020 को लिया गया ।
69. ^ "आत्म निर्भर भारत अभियान: स्कूल-कॉलेज से शुरू हो गया है । " पत्रिका समाचार (हिंदी में) । 29 सितंबर 2020 को लिया गया ।
70. ^ "कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बना" । द न्यू इंडियन एक्सप्रेस । 15 सितंबर 2020 को लिया गया ।
71. ^ दिल्ली नवम्बर 20, इंडिया टुडे वेब डेस्क न्यू; 20 नवंबर, 2020अपडेट किया गया; पहली, 2020 01:22। एनईपी को 2020 तक चरणों में लागू किया जाएगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं । इंडिया टुडे ।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411025 |

72. ^ फनिहारन, वीआरसी (8 अगस्त 2020)। "तेलंगाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए तैयार है" । www.thehansindia.com ।
73. ^ "एनईपी 2020: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया" । हिंदुस्तान टाइम्स । 21 अगस्त 2020 ।
74. ^ स्टाफ रिपोर्टर (8 सितंबर 2020)। "एनईपी 2020 को अक्षरशः लागू किया जाएगा: जगन" । द हिंदू । आईएसएसएन 0971-751X ।
75. ^ "एनईपी 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा कहते हैं" । हिंदुस्तान टाइम्स । 7 अक्टूबर 2020 ।
76. ^ इंडियन टुडे वेब डेस्क (21 अगस्त 2020), "एनईपी 1

INNO SPACE

SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466

9710 583 466

ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com